AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

NÙkhlx< ds 'kkldh; o v'kkldh; Mh-,y-,M- çf'k{k.k laLFkkvksa dk *lEiw.kZ xq.koÙkk eY;kadu* % vkèkkfjd vuqn'kZRed o vU; lqfoèkkvksa ds fo'ks"k lanHkZ esa

M,- ç—fr tsEl]
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग,
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

lR;çdk'k ;kno]
शोधार्थी, शिक्षा विभाग,
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

'kks/k lkj

शिक्षण जैसे उत्तम कार्य में शिक्षक की भूमिका केन्द्रीय हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षक से हमारी अपेक्षाएँ बढ़ गयी है, आज उसे जहां स्वयं विद्यार्थी, समाज, शाला, व्यवसाय इत्यादि के प्रति समर्पित होना है, वहीं विषय–विशेषज्ञ, चिंतक के रूप में भी अपने को साबित करना है। वास्तव में अध्यापक ही संस्था द्वारा प्रदत्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता हैं। शिक्षको के प्रशिक्षण मे प्रयोगात्मक कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध निष्कर्षो के प्रकाश में राज्य की शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रयोगात्मक कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उसमें अनुभूत समस्याओ के निराकरण के उन्नयन में दिशा–निर्देशन प्राप्त होगा और शिक्षको को उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाया जा सकेगा।

eq[; 'kCn

f'k{kd] izf'k{k.k] xq.koRrk-

इक्कीसवीं शताब्दी का भारत तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। उसको इस विकास–पथ पर आगे बढ़ाने हेतु एक कुशल मानव संसाधन के रूप में योग्य नागरिकों की आवश्यकता है। उनके इस आवश्यकता की पूर्ति देश की अच्छी शिक्षा–व्यवस्था तथा उन्नत शिक्षक–शिक्षा के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सभी चुनौतियों का सामना करना संभव हो सकेगा। शिक्षा की दृष्टि से ''प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण'', ''गुणवत्तापूर्ण सभी के लिए शिक्षा'', आदि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख लक्ष्य रहें हैं। इसी क्रम में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना, आज उनका मौलिक अधिकार बन गया है, साथ ही यह लक्ष्य देश का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी हो गया है। व्यवहारिक रूप से देश के शैक्षिक समस्याओं की जांच करने वाले प्रत्येक शिक्षा आयोग ने अध्यापकों की दशा की ओर विशिष्ट ध्यान दिया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने भी कहा है कि हम इस बात से पूरी तरह सहमत है कि आमूलचूल शैक्षिक पुनर्गठन में अध्यापक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा आयोग (1964–66) के अनुसार शिक्षा की विशिष्टता तथा गुण को प्रभावित करने वाले एवं राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी विभिन्न घटकों में निःसंदेह रूप से शिक्षकों की योग्यता एवं उनके गुण सर्वाधिक प्रभावकारी है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इन अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक कुशल शिक्षक तैयार करना होगा और यह तभी संभव है जब देश में शिक्षक को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान किया जाय।

NÙkh lx< e 'kkldh; ,o v'kkldh; Mh-,y-,M- çf'k{k.k lLFkkvk dh fLFkfr

छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर, छत्तीसगढ, 2018 के आंकड़ों के अनुसार 27 जिलों में कुल 21 शासकीय एवं 68 अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ संचालित हो रही हैं जिनमें दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का पाठ्यक्रम संचालित कर प्रारंभिक शालाओं हेतु प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

lEi.k x.koÙkk eY;kdu

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना नई दिल्ली 28 नवंबर 2014 जिसका प्रकाशन भारत राजपत्र (भाग–3 खण्ड चार) के पृष्ठ 13 परिशिष्ट–2 में अंकित प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यचर्चा के मानदंड और मानकों में दिए गये विभिन्न मुद्दों यथा इण्टर्नशिप को गुणवत्ता सूचकांक मानकर (Quality Indicators) शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएं का सम्पूर्ण गुणवत्ता का मापन किया गया है। प्रस्तुत शोध में सम्पूर्ण गुणवत्ता मापन/मूल्यांकन का यही अभिप्राय है।

vè; ;u dk vkfpR;

आज के युग मे क्षमतावान शिक्षकों की महती आवश्यकता है विशेषकर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के विषय में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि वर्तमान में पूरे शिक्षा जगत का ध्यान प्रारंभिक शिक्षकों की ओर आकृष्ट हो रहा है। लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर बिलासपुर गुरूवार 9 नवंबर, 2017 के पृष्ठ 18 पर मुद्रित समाचार के अनुसार "शिक्षा के अधिकार कानून के तहत मार्च 2019 के पहले सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को डी.एल.एड. यानी डिप्लोमा इन इलिमेण्ट्री एजुकेशन का दो साल का कोर्स करना होगा। केन्द्र सरकार ने चाहे वह निजी हो, या फिर शासकीय या अर्द्धशासकीय या अनुदान प्राप्त, सभी स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डी.एल.एड. पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्स न करने पर शिक्षक अध्यापनकार्य से वंचित हो जायेंगे और उनके सामने रोजी–रोटी का प्रश्न खड़ा हो जायेगा। "इस समाचार के अनुसार डाईट एवं डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं का महत्व प्रारंभिक शिक्षा जगत में अचानक बढ़ गया है इसलिए डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं ने प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति को सकारात्मक बना दिये है। ऐसे सभी वे उम्मीदवार जो इस स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं, वे सुविधा संपन्न प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर अध्यापक बनने की पात्रता पा लेना चाहते हैं। डी.एल.एड. पाठयक्रम के प्रारंभ में प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति, प्रशिक्षण पूरा करने पर प्राप्त अभिवृत्ति में परिवर्तन आना, प्रशिक्षण के प्रति अत्यंत सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास का संकेत देता है और सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता निरुपित करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता व सार्थकता उपरोक्त गद्यांशों के प्रकाश में रेखांकित होती है।

vè; ;u dk mís';

- शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं की आधारिक सुविधाओं की तुलना करना।
- शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता की तुलना करना।
- शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं की अन्य सुविधाओं (फर्निचर, महिला, पुरूष) के लिए अलग कक्ष, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ परिसर, अशक्त व्यक्तियों के लिए अनुकुल व्यवस्था, आदि की तुलना करना।

vè; ;u dh ifjdYiuk

H_1 शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आधारिक सुविधाओं में अंतर पाया जाता है।

H_2 शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता में अंतर होता है।

H_3 शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में मानक के अनुसार निर्धारित अन्य सुविधाओं की उपलब्धता में अंतर होता है।

'kkèk çdYi

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णात्मक अध्ययन है जिसमें सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

'kkèk U;kn'k

छत्तीसगढ़ के 27 जिलां में 21 शासकीय डी.एल.एड. एवं 68 अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाएँ वर्तमान में संचालित हैं। अध्ययन हेतु 09 शासकीय एवं 09 अशासकीय संस्थाओं को उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया द्वारा चुना गया है, जिसके तहत जिस जिले में शासकीय डी.एल.एड प्रशिक्षण संस्थाएॅं हैं उन्हीं जिलो की अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाएँ न्यादर्श में शामिल है, तथा प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रथम वर्ष से 25 एवं द्वितीय वर्ष से 25 प्रशिक्षार्थी, 07 शिक्षक–प्रशिक्षक एवं 01 प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष को प्रश्नावली भरने हेतु चयन किया गया।

'kkèk pjkd

प्रस्तुत अध्ययन में चर एवं उनके स्तर निम्नानुसार हैः

Lor= pj

(i) डाईट / डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं मानक के अनुपालन के स्तर।

(ii) lLFkkvk d çdkj% शासकीय एवं अशासकीय।

vkfJr pj

डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सम्पूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन इस अध्ययन के आश्रित चर है।

vè;;u e ç;ä 'kkèk midj.k

शैक्षिक गुणवत्ता मापनी प्रश्नावली–शैक्षिक गुणवत्ता मापनी प्रश्नावली का निर्माण शोध–निर्देशक एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों एवं मानकीकृत दिशानिर्देशों के आधार पर शोधकर्ता द्वारा स्वयं किया गया है।

ekiuh dk çk:i

मापनी का स्वरूप लिकर्ट आधारित कथनों पर आधारित है। प्रस्तुत आयाम भारत के राजपत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना नई दिल्ली 28 नवम्बर, 2014 के परिशिष्ट–02 में उल्लेखित प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त करने वाले प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पाठ्यचर्या के मानदंड और मानक के अनुसार चयनित हैंः

1. आधारिक सुविधाएं
2. अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता
3. अन्य सुविधाओं की उपलब्धता

ifjdYiukvk dk ijh{k.k ,o 0;k[;k

$\mathbf{H_1}$ शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आधारिक सुविधाओं में अंतर पाया जाता है।

उपरोक्त परिकल्पना के परीक्षण हेतु "t" की गणना निम्नांकित सारणी के अनुसार प्राप्त हुई हैः

lkj.kh Øekd 01% आधारिक सुविधाओं संबंधी उपलब्धता पर शिक्षकों एवं प्रशिक्षार्थियों के मत संबंधी परीक्षण परिणाम

*Significant

चरांक	संस्थाएं	N	M	SD	"t"	व्याख्या
आधारिक सुविधाएं	शासकीय डी.एल.एड. संस्थाएं	487	14.09	3.53	6.507*	P<.05
	अशासकीय डी.एल.एड. संस्थाएं	513	15.34	2.47		

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

fu"d"kZ

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर गणना से प्राप्त "t" का मान (6.507) सारणीगत मान (1.96) से अधिक हैं। अतः शोध परिकल्पना H_1 स्वीकृत होती है। प्राप्त परिणाम के आधार पर हम कह सकते है कि शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आधारिक सुविधाओं में अंतर पाया जाता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अशासकीय डी.एल.एड. संस्थाओं की आधारिक सुविधाएँ शासकीय डी.एल.एड. संस्थाओं की आधारिक सुविधाओं से अधिक अच्छी है।

H_2 शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता में अंतर होता है।

उपरोक्त परिकल्पना के परीक्षण हेतु "t" की गणना निम्नांकित सारणी के अनुसार प्राप्त हुई हैः

lkj.kh Øekd 02% अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता पर उत्तरदाताओं के मत संबंधी परीक्षण परिणाम

*Significant

चरांक	संस्थाएं	N	M	SD	"t"	व्याख्या
अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता	शासकीय डी.एल.एड. संस्थाएं	487	10.62	2.21	2.547*	P<.05
	अशासकीय डी.एल.एड. संस्थाएं	513	10.97	2.13		

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

fu"d"kZ

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर गणना से प्राप्त "t" का मान (2.547) सारणीगत मान (1.96) से अधिक हैं। अतः शोध परिकल्पना H_2 स्वीकृत होती है। प्राप्त परिणाम के आधार पर हम कह सकते है कि शासकीय और अशासकीय डी.एल.एड. संस्थाओं में एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता में अंतर पाया जाता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अशासकीय डी. एल.एड. संस्थाओं में अनुदेशनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता शासकीय डी.एल.एड. संस्थाओं में अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता से अधिक अच्छी है।

H_3 शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में मानक के अनुसार निर्धारित अन्य सुविधाओं की उपलब्धता में अंतर होता है।

उपरोक्त परिकल्पना के परीक्षण हेतु "t" की गणना निम्नांकित सारणी के अनुसार प्राप्त हुई हैः

lkj.kh Øekd 03% अन्य सुविधाओं की उपलब्धता पर उत्तरदाताओं के मत संबंधी परीक्षण–परिणाम

*Significant

चरांक	संस्थाएं	N	M	SD	"t"	व्याख्या
अन्य सुविधाओं की उपलब्धता	शासकीय डी.एल.एड. संस्थाएं	487	10.47	2.55	0.945*	P<.05
	अशासकीय डी.एल.एड. संस्थाएं	513	10.61	2.11		

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

fu"d"kZ

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि शासकीय एवं अशासकीय दोनों ही डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में अन्य सुविधाएं जैसे फर्नीचर व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, महिला एवं पुरूष हेतु अलग–अलग कामॅन रूम एवं शौचालय की व्यवस्था इत्यादि की उपलब्धता समान रूप से है। आंकड़े यह स्पष्ट करते है कि गणना से प्राप्त "t" का मान .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर सारणीगत मान से कम है, इनमें अंतर नहीं पाया गया, अर्थात् शोध परिकल्पना H_3 अस्वीकृत होती है।

foospu

परिकल्पना क्रमशः H_1, H_2, H_3 के निष्कर्षो की विवेचना निम्नानुसार की जाती है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन एजुकेशन (अप्रैल 2004, पृष्ठ 462) में सत्यभूषण जी का प्रतिवेदन है, कि विभिन्न राज्य सरकारो ने अपने–अपने राज्यों में डाईट्स का गठन अपने राज्य की आवश्यकता, अनुभव के अनुसार किया है। उनके राज्य में पूर्व से संचालित प्रारंभिक शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थाओं का ही उन्नयन कर उन्हें डाईट्स का रूप दे दिया है, इसलिये संसाधनों, सुविधाओं, मानको व कार्यप्रणाली में डाईट्स के द्वारा अपेक्षित स्तर नहीं पाया जा सका है। न्यूपा तथा एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा डाईट्स के मूल्यांकनात्मक प्रतिवेदनों के अनुसार भी विभिन्न राज्यों के डाईट्स ने अपने लक्ष्य तथा दूरदृष्टि को नहीं प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के डाईट्स के विषय में यह निष्कर्ष सत्य प्रतीत नही होते हैं।

राज्य की अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में संस्था हेतु पर्याप्त भूमि, कक्षा का आकार मानक अनुरूप, पुस्तकालय कक्ष, प्राचार्य कक्ष, स्टॉफ रूम, स्टोर कक्ष इत्यादि आधारिक सुविधाएं अच्छी है। पाणिग्रही (2010) के अध्ययन निष्कर्षों से इसकी पुष्टि होती है इन्होने अशासकीय एवं स्ववित्तपोषी शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन किया और पाया कि बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के उपलब्धता और कार्यक्षमता के मामले में यह बेहतर है। कुछ शासकीय प्रशिक्षण संस्थायें BT का उन्नयन स्वरूप बनी है, जबकि कुछ नए डाईट्स विकसित किए गए है इसलिए इनमें आधारिक सुविधाओं में अशासकीय संस्थाओं की तुलना में कुछ कमी पाई गई है। इसी तरह पुस्तकें, जर्नल चार्ट, चित्र, स्लाइड, फिल्म, समाचार पत्र इत्यादि अनुदेशात्मक सामग्री भी अशासकीय संस्थाओं में शासकीय संस्थाओं से ज्यादा अच्छी देखी गई है जबकि संस्था में पानी व्यवस्था, महिला, पुरूष शौचालय व्यवस्था, संस्था का परिसर, कॉमन रूम, प्रिंटर की सुविधा इत्यादि अन्य सुविधाएं शासकीय अशासकीय संस्थाओं में समान रूप से देखी गई है।

इसी तरह के अध्ययन के निष्कर्ष Hkkfed (2015) ने गुजरात के डाईटों की वर्तमान स्थिति और कार्यप्रणाली पर प्राप्त किये थे, जहां कुछ डाईट्स के पास निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार पर्याप्त भूमि नहीं थी किन्तु अधिकांश डाईट्स में ढांचागत सुविधायें पायी गयी अकादमिक स्टॉफ की कमी, विज्ञान प्रयोगशाला का अभाव पाया गया, कुछ डाईट्स में शायद ही कभी प्री–सर्विस एवं सेवारत प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों ने प्रयोगशाला का उपयोग किया था, विज्ञान प्रयोगशाला में पानी की सुविधा, वॉशवेसिन की सुविधा बहुत अच्छी नहीं थी। पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार पाया गया, डाईट्स में चार्ट बहुत कम उपलब्ध थे। सेमिनार रूम में फर्नीचर, डिस्प्ले बोर्ड, ऑडियो

कैसेट प्लेयर, टी.वी. की उपलब्धता पर्याप्त थी। डाईट्स में कम्प्यूटरों, प्रिंटर, की अच्छी सुविधा थी, छात्रावास सुविधा, खेल का मैदान डाईट्स में उपलब्ध थे।

इस तरह मिश्रित परिणाम के निष्कर्ष हमें प्राप्त होते है किन्तु यह स्पष्ट प्रतीत है कि शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता में क्रमशः सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं।

l UnHk l ph

1. चन्द्रशेखर, के. (2000): एन इवेल्यूवेटिव स्टडी ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम इन आन्ध्र प्रदेश, पी–एच.डी. थिसिस–एजुकेशन, श्री वेंकेटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति.
2. चन्द्रशेखर, के. (2017) : ''टीचर एजुकेशन्स परसेप्सन्स ऑफ डाईट्स फेसिलिटीज एण्ड दियर रिलेसन्स टू सर्टेन पर्सनल एण्ड डिमोग्राफिक वैरियेबल्स'' *पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन,* बड़ौदा, वाल्यूम 23(2), पृष्ठ 92–104.
3. दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, बिलासपुर, गुरूवार 9 नवंबर, 2017 पृष्ठ 18.
4. दास आर.सी. एवं जंगीरा एन.के. (2004) : 'ए ट्रेण्ड रिपोर्ट, टीचर एजुकेशन',थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन,एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली,पृष्ठ : 782–789.
5. डेलर्स, जे. एवं अन्य (1998) : ''क्वालिटी टीचर्स, लर्निंगः दी ट्रेजर विदिन' रिपोर्ट टु यूनेस्को ऑफ दी इण्टरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फार दी ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी, पेरिस, यूनेस्को : कोटेड बाई इन दी *इण्डियन्स जर्नल फॉर टीचर एजुकेशन,* एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली, वाल्यूम 1(1) : 146.
6. दीपा, कृष्णा एवं सरोज, आनन्द (2006) : गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षक–प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका, अन्वेषिका 3(2) :75–80.
7. मुखोपाध्याय, मारमर (2009) : शिक्षा में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन, डायमण्ड पॉकेट बुक (प्रा.) लि., नई दिल्ली

****